to prove to be the best not in India alone, but all over the world.

Australia, as I have already stated, is known to have succeeded in evolving sugarcane varieties having the highest sucrose content in the world, but the per acre yield in Australia is 25 to 30 tons. The variety to which I am referring is giving very high yields, as high as 80 to 90 tons per acre. Only last year, in my own farm I had planted this variety on a plot of six acres. I have got 92 tons per acre average yield. Hundreds of farmers are getting even more. Only yesterday I received a journal which is conducted by Dr. D. R. Gadgil, and in that a statement appears that four agriculturists who had planted this variety of Co. 740, got yields as follows:

Shri E. M. Bhogale, Malar, Baramati Taluk, Poona Dt. per acre yield 238 tons.

Shri Shinkre (Marmagoa): Maunds or tons?

Shri Shinde: Tons. Nowhere in the world has it happened. That is why I am praising all the valuable work that is being done by our scientists.

Shri Shinkre: Then, the Food Ministry should adopt it immediately.

Shri Swaran Singh: The farmers are adopting it.

Shri Shinde: It depends on environmental factors also.

The others are:

Shri S. V. Rauth, Malinagar, Malasiras Taluk, Sholapur Dt. Per acre yield 133 tons

Shri K. L. Shinde (not myself), Rahata, Kopargaon Taluk, Ahmednagar Dist. Per acre yield 131 tons.

Shri V. D. Dhopate, Kahale, Baramati Taluk, Poona Dt. Per acre yield 134 tons.

This will show what a wonderful job is being done by our scientists, and they really deserve to be congratulated by this House, and I feel that hon. Members will share my sentiments in this respect.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): Can you give an idea about the sugar content?

Shri Shinde: The recovery is anywhere between 12 and 13 per cent, but the actual total sugar in cane may come to about 15 to 16 per cent. It is higher than the Pravara variety, and the per acre yields are far higher than Hawai. But the main problem of sugarcane and other research activities in India is how to carry successfuly the results of research to the farm on a large scale. The Ford Foundation Team has expressed the view and pointed out that India's agricultural research knowledge is already adequate to permit a very large expansion in production and productivity per acre. The basic problem is to extend the known and tested practices to cultivators and ensure their adoption.

With these few remarks, I thank the Chair for giving me an opportunity to express myself.

Mr. Deputy-Speaker: Before I call the next Member, Shri Hathi will give some information to the House.

17.36 hrs.

STATEMENT *RE*: REFERENCE OF MATTER BY PRESIDENT TO SUPREME COURT UNDER ARTICLE 143 OF CONSTITUTION

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): Sir, I am sorry to take the time of the House, but I thought that it would be better if I show that courtesy to the House and inform the House that the President has been pleased to make

[Shri Hathi.]

a reference to the Supreme Court under article 143 of the Constitution in regard to the conflict of powers and jurisdiction between the Uttar Pradesh State Legislature and the High Court of Uttar Pradesh which has recently occurred. I thought I might give that information to the House.

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE—*contd.*

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री शिन्दे का भाषण हुआ । उन्होंने अपने भाषण में अनेकों सफलताओं का दिग्दर्शन हमें कराया लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह सब आपकी सफलताएं जो आपने हमें अभी बतलाई वे कागजों में ही रहने वाली हैं क्योंकि किसानों तक वह पहुंच नहीं पाती हैं। यदि वह किसानों तक पहुंची होतीं तो आज यह जो गुड़ की तकलीफ है और शक्कर की तकलीफ है वह तकलीफ़ नहीं होने वाली थी । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो हमारे मंत्रियों का अभ्यास हो गया है कि तरह तरह के आंकड़ों को दिखा कर इस सदन के लोगों को सन्तुष्ट करा दो, उनके इस अभ्यास से नतीजा उल्टा होने वाला है । अब चाहे वह सरदार साहब हों, चाहे डा० राम सुभग सिंह हों अथवा टामस साहब हों, प्रश्न यह है कि यदि आप आंकड़ों में ही उलझते और दूसरों को उलझाते रहेंगे तो यह खाद्य समस्या कभी हल होने वाली नहीं है । यह जो आंकड़ों का जाल है वह इस खाद्य मंत्रालय की रिपोर्ट में खूब देखने को मिलता है लेकिन जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें यह कहीं जिक्र नहीं है कि किस प्रकार से हर एक प्रदेश की अवस्था चल रही है, कौन सा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और कौन सा प्रदेश पीछे है और उन प्रदेशों में कौन सा जिला आगे बढ़ रहा है और कौन सा जिला पीछे चल रहा है इसका कहीं जिक्र नहीं है । हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि पैकेज प्रोग्राम जिन जिलों में चलाया जाता है वहां की जब रिपोर्टें आती हैं, जब वह जांच करने के लिये गये और उस बारे में रिपोर्ट की है तो वह उसमें यह नहीं बतला पाये कि कहां काम ठीक चल रहा है और कहां ठीक नहीं चल रहा है, केवल यह लिखा है कि दो, तीन वर्ष में इसका कोई नतीजा निकल सकेगा इसकी कोई आशा नहीं करनी चाहिए । कम से कम वह यही बतलाते कि कितने वर्षों में उसका नतीजा निकलेगा लेकिन वह भी इसमें नहीं लिखा है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो एक जाल है रिपोर्ट करने का इस जाल से तो हम और ही उलझ जाते हैं, सुलझ नहीं सकते हैं चाहे हम फूड डिबेट १० घंटे का कर लें और चाहे १२ घंटे का कर लें ।

17.28 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

सभापति महोदय, वास्तव में खाद्य मंत्रालय में पिछले सत्तरह वर्षों में बड़े बड़े माहिर आये हैं और अभी भी विद्यमान हैं लेकिन तो भी आज तक वे महानुभाव इस देश की खाद्यान्न समस्या को सफलतापूर्वक हल नहीं कर पाये हैं । यहां पर तो वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की । मर्ज बढ़ता ही जा रहा है हालांकि दवा करने की कोशिश भी की जा रही है । ऐसा क्यों हो रहा है और यह मर्ज क्यों नहीं खत्म हो रहा है ? वह इस कारण है कि मर्ज की जड़ को हम लोग नहीं पकड़ते हैं । हमारी जो ग्राम योजनायें होनी चाहिएं और जो कि ग्रामो का आधार बननी चाहिएं वह ग्राम योजनाएं नहीं बनती हैं । गांव वालों को मालूम नहीं है कि हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं लेकिन सरदार साहब के आंकड़े के अनुसार बढ़ गया है । गांव वालों के पास इस वक्त कोई तरीका नहीं है कि वे कभी बैठ कर इस बारे में सोचें । आज-कल होता यह है कि गांवों में इतना फ़र्टलाइजर गया इतने कुएं खोद दिये गये, इतना बीज दिय'